जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरो में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते।
–अज्ञात।

विचार-प्रवाह देहरादून, बुधवार, 8 दिसंबर 2021

पेज थ्री
www.page3news.in

बढ़ती गैर–बराबरी की ओर दें ध्यान

रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा ऊपर की दस फीसदी आबादी के हाथों में सिमट गया है। निचले हिस्से की 50 फीसदी आबादी के पास महज दस फीसदी संपत्ति है। गांवों के मुकाबले शहरों में यह विभाजन और तीखा नजर आता है।

नवीन शाह।।

नैशनल सैंपल सर्वे द्वारा करवाए गए ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 की रिपोर्ट ने एक बार फिर देश में लगातार बढ़ती गैर–बराबरी की ओर ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा ऊपर की दस फीसदी आबादी के हाथों में सिमट गया है। निचले हिस्से की 50 फीसदी आबादी के पास महज दस फीसदी संपत्ति है। गांवों के मुकाबले शहरों में यह विभाजन और तीखा नजर आता है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अमीर दस फीसदी लोगों के पास 50.8 फीसदी संपत्ति है वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 55.7 प्रतिशत पाया गया है। इस विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के अलग–अलग कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर बारीकी से विचार होना चाहिए, लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया जिन इलाकों में ज्यादा तेज रही, वहां असमानता का अनुपात भी ज्यादा है। इस तथ्य के अपने गहरे निहितार्थ भले हों, लेकिन यह अपने आप में कोई नई बात नहीं है।

इससे पहले भी समय–समय पर आने वाली अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह तथ्य उजागर होता रहा है कि भारत में विकास की गति तेज होने के बाद भी पिछले ढाई–तीन दशकों में विषमता में तेज बढ़ोतरी हुई है।

क्रेडिट सुईस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 में तो कहा गया था कि देश की सबसे अमीर एक फीसदी आबादी के पास 51.5 फीसदी संपत्ति इकट्ठा हो गई है। ऐसी अलग–अलग रिपोर्टों में प्रतिशत का थोड़ा–बहुत अंतर कभी–कभार दिखता है तो उसकी एक वजह यह होती है कि उनमें संपत्ति की गणना के पैमाने अलग–अलग होते हैं। लेकिन इस तथ्य की पुष्टि इन तमाम रिपोर्टों से होती है कि भारतीय समाज में विषमता सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है।

वैसे यह रुझान अपने देश तक सीमित नहीं है। किसी भी समाज में अगर तेजी से समृद्धि आती है तो यह संभावना रहती है कि शुरू में संपत्ति आबादी के कुछ खास हिस्सों के हाथों में आए, जिससे विषमता बढ़ी हुई दिखने लगे। अपेक्षा यह रहती है कि बाद के दौर में यह धीरे–धीरे समाज के अन्य तबकों तक पहुंच कर उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा करेगी। इसी बिंदु पर योजनाओं की भूमिका अहम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपनी स्वाभाविक गति में यह समृद्धि समाज के अन्य तबकों तक पहुंच रही है या नहीं। अगर नहीं पहुंचती है तो यह देखना होता है कि उसकी गति को बाधित करने वाले कारक कौन से हैं और उन्हें दूर करने के क्या इंतजाम हो सकते हैं। एनएसएस के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में सरकार को ऐसे इंतजामों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

शिक्षा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।
एक चमकता हुआ पत्थर भर है, जिसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं। हम इससे अपनी भूख नहीं मिटा सकते। अगर यही हीरा किसी जौहरी को मिला होता तो यह उसके लिए लाखों रूपयों का होता। हमारे लिए तो जौ और मक्का इस चमकते हुए हीरे से अधिक मूल्यवान हैं।" यह सुनकर उस मुर्गे ने हीरा वहीं कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया और आगे भोजन की तलाश में बढ़ गया। शिक्षा हर वस्तु हर प्राणी के लिए मूल्यवान नहीं होती। अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों को सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, "क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी?"

संपादकीय

प्रक्रिया से निराशा

ग्लासगो सम्मेलन से फिर भी कुछ ऐसी बातें सामने आई जो आने वाले समय के लिए अहम होंगी। एक काम तो यही हो सकता है कि पैरिस एग्रीमेंट को अमल में लाने की रूल बुक पर मुहर लग जाए। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई नया प्लान बनाएं, जो ज्यादा भरोसेमंद हो। विकसित देशों के लिए भी साल 2030 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना संभव नहीं दिख रहा, लेकिन अगर वे ऐसा कर ले जाएं तो विकासशील देशों को भी एमिशन घटाने में तेजी दिखानी होगी। इस मोर्चे पर विकसित देशों की संजीदगी से भरोसा कायम करने में मदद मिल सकती है। ग्लासगो सम्मेलन के लिए रुटेलदट्रुथ एक पॉप्युलर हैशटैग है। इसमें नौजवान कार्यकर्ताओं की हताशा झलक रही है। वे बातचीत की लंबी खिंचती प्रक्रिया से निराश हैं। वे कहते हैं, ग्लासगो में दुनियाभर के नेताओं को सच बोलना चाहिए। तीन दशकों से जलवायु परिवर्तन के मसले पर बातचीत हो रही है, लेकिन बेईमानी और गलतबयानी के कारण ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। ऐसे में ग्लासगो सम्मेलन का क्या मतलब है? क्या इससे कुछ हाथ आ सकता है? इस सम्मेलन से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शासन के दौरान जलवायु परिवर्तन के मसले पर तमाम देशों में मतभेद बढ़े।

जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कोयले का उपयोग घटाना और फिर बंद कर देना जरूरी है। लेकिन फायदे की चीज तो नैचरल गैस भी नहीं है। बिजली बनाने में उसका उपयोग भी रोकना होगा।

2050 तक नेट जीरो!

चंद्र भूषण।।

जलवायु परिवर्तन के मसले पर एक बड़ी जुटान हो रही है ग्लासगो में। सीओपी26 यानी ट्वेंटी सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में दुनिया के 100 से ज्यादा बड़े नेता पहुंचे। 31 अक्टूबर से शुरू हुई चर्चा दो हफ्तों तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी अपनी बात रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मौसम से जुड़े मसले पर पहली बार ऐसी हलचल दिख रही है। 1997 में क्योटो, 2009 में कोपेनहेगन और 2015 में पैरिस में इसी तरह के सम्मेलन हुए थे। मैं भी इनमें से दो में शामिल हुआ। खूब बातें हुईं, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्लासगो का आयोजन भी उसी दिशा में जाता दिखा।

पिछले कुछ महीनों में तमाम देशों ने अपनी मांगों की लंबी लिस्ट पेश की है। ब्रिटेन का जोर इस पर है कि कोयले से बिजली बनाने पर रोक लगाने वाले कदम उठाए जाएं। अमेरिका चाहता है कि नेट–जीरो डील की जाए यानी 2050 तक एमिशन जीरो करने की पॉलिसी पक्की कर ली जाए। वहीं महासागरों के किनारे मौजूद देशों के संगठन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की मांग ऐसे उपाय करने की है, जिनसे दुनिया के तापमान में डेढ़ डिग्री सेल्सियस की कमी आए। पिछड़े देशों का कहना है कि जिन देशों ने बड़े पैमाने

पर प्रदूषण फैलाया है, वे इससे हुए नुकसान की भरपाई करें। वे अरबों डॉलर का हर्जाना मांग रहे हैं। वहीं, लाइक–माइंडेड डिवेलपिंग कंट्रीज यानी एक साझा सहमति बना चुके देशों के ग्रुप का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए 100 अरब डॉलर का फंड बनाया जाए। मांगें चाहे जो भी हों, इनके लिए ग्राउंड लेवल पर कोई काम हुआ नहीं है। ऐसे में आसार यही हैं कि इन कागजों का पुलिंदा रद्दी की टोकरी में जाएगा।

मसलन, कोयले से बिजली बनाने पर रोक के प्रस्ताव को ही लीजिए। ब्रिटेन जोर दे रहा है कि साल 2030 तक विकसित देशों में पूरी तरह से रोक लग जाए और बाकी दुनिया में 2040 तक बैन लगा दिया जाए। लेकिन कोयले का उपयोग करने वाले अधिकतर देश इसके पक्ष में नहीं हैं। भारत और चीन कोयले का उपयोग करने वाले दो बड़े देश हैं। ये भी ब्रिटेन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। विकसित देश तो मुख्य रूप से नैचरल गैस से बिजली बना रहे हैं। लेकिन भारत में 70 प्रतिशत बिजली कोयले से बनाई जाती है। चीन में भी आंकड़ा 62 फीसदी का है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कोयले का उपयोग घटाना और फिर बंद कर देना जरूरी है। लेकिन फायदे की चीज तो नैचरल गैस भी नहीं है। बिजली बनाने में उसका उपयोग भी रोकना होगा। तमाम देशों का कहना है कि एक को बंद करें और दूसरे को चालू रखें, यह ठीक बात नहीं है। पेच यह भी है कि कोयले का उपयोग घटाने और बंद करने की राह पर चला कैसे जाएगा, इस बारे में कोई ठोस चर्चा भी नहीं हुई है। यह भी तय नहीं है कि कोयले की खदानों और बिजली के कारखानों को बंद करने की भरपाई के लिए पैसे कौन देगा।

भारत जैसे देशों में अच्छी–खासी आबादी का जीवन कोयले पर टिका है। ऐसे में खदानों वाले इलाकों में आजीविका के दूसरे उपाय करने में काफी निवेश करना होगा। लेकिन यह कैसे होगा, वैश्विक स्तर पर कौन सहयोग करेगा, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रस्ताव का क्या होना है, इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए।

सूडोकु नवताल-5345

★★★★☆ कठिन

		5			3			
	2			9	5			
9						6		
							3	5
	6						7	
4	8							
		7						3
			2	4			9	
			8			2		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5344 का हल

4	2	5	8	6	1	9	7	3
7	3	1	9	4	2	8	5	6
6	9	8	7	3	5	4	2	1
1	6	2	3	8	9	5	4	7
9	4	3	5	1	7	6	8	2
8	5	7	4	2	6	3	1	9
2	1	9	6	5	8	7	3	4
5	7	4	1	9	3	2	6	8
3	8	6	2	7	4	1	9	5

अपना ब्लॉग

जान–माल का बड़ा नुकसान हो रहा है

मोहन। नुकसान और हर्जाने वाले मसले पर भी मतभेद हैं। जलवायु परिवर्तन का असर विकासशील देशों में साफ दिख रहा है। जान–माल का बड़ा नुकसान हो रहा है। बाढ़ और दूसरी आपदाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। राहत कार्यों और नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में बड़ा पैसा लग रहा है। इन देशों का कहना है कि जिन देशों ने बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया है, वे इस नुकसान की भरपाई करें। लेकिन विकसित देश इस बारे में बात करने तक को तैयार नहीं। वे कह रहे हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह मसला लेकिन है गंभीर और इसके चलते ग्लासगो में पूरी बातचीत ही ट्रैक से हट सकती है। दरअसल सभी बड़े प्रस्तावों पर इसी तरह के मतभेद हैं। फिर कोविड महामारी के दौरान जिस तरह विकसित देशों ने अपने लोगों के लिए वैक्सीन रिजर्व कीं और बाकियों को उनके हाल पर छोड़ दिया, उससे भी माहौल खराब हुआ।